उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सूभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 08 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–06(02/25)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से गुरूवार को देर सायं मुख्यमंत्री आवास में श्री महन्त देवेन्द्र दास ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस वृद्धि से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने श्री महन्त देवेन्द्र दास को आश्वस्त किया कि फीस कमेटी की रिपोर्ट व इस संबंध में प्रचलित एक्ट आदि का संज्ञान लेते हुए शीघ्र ही प्रदेश के सभी निजी मेडिकल कॉलेज के संस्थानों के प्रमुखों व शासन के उच्चाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर इस संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय सहयोग के लिये श्री महन्त देवेन्द्र दास का आभार व्यक्त करते करते हुए उनसे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सविधाओं के विकास में सहयोग की भी अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण अभियान में भी महन्त श्री देवेन्द्र दास से सहयोग की अपील की।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत व गुरू राम राय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.पीताम्बर प्रसाद ध्यानी भी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 08 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–05(02/24)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इस सम्बंध में पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।

गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने निर्देश दिये कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये सम्बंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें तथा बढती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कारगर प्रयास सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये जो भी कार्ययोजना बनायी जाती हो, उस पर अविलम्ब कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो रोड़ सेफ्टी फंड से परिवहन विभाग को और अधिक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि वाहनों की चेकिंग आदि के लिये आवश्यक संसाधनों की कमी न रहें। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी बैरियरों पर वाहनों की प्रॉपर चेकिंग की जाए। ओवर लोडिंग को सख्ती से रोका जाए। ड्राइवर शराब पीकर वाहन न चलायें। ड्राइवर की बगल वाली सीट पर एक से अधिक व्यक्तियों को बैठने से रोका जाए। यदि पुलिस व परिवहन विभाग आपसी तालमेल से इस दिशा में प्रभावी पहल करेगी, तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में कमी आयेगी। उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने के लिये भी जनजागरण के प्रति विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही सभी जनपदों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ रोड सेफ्टी के सम्बंध में की जा रही कार्यवाही के संबंध में वीडियोकांफ्रेंसिंग भी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये जनता एवं अधिकारियों से इस संबंध में अपने–अपने सुझावों से अवगत कराने की भी बात कही है। यातायात नियमों के अनुपालन के अलावा ओवरलोडिंग को रोकने में भी पुलिस को जिम्मेदारी दी जाए। शहरों में ट्रेफिक सुधारों के प्रति भी विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये है। इसके साथ ही सैटेलाइट बेस चालान क्रासिंगो पर ट्रेफिक के दबाव को कम करने आदि की दिशा में भी अन्य राज्यो की भांति यहां भी सम्भावनायें तलाशी जाए। राज्य में सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हो तथा शहरों को ट्रेफिक जाम से निजात मिल सकें, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की भी बात कही।

बैठक में सचिव परिवहन श्री डी.सेंथिल पाण्डियन, अपर सचिव श्री चन्द्रेश कुमार, निदेशक ट्रेफिक श्री केवल खुराना, निदेशक आई.टी.डी.ए. श्री अमित सिन्हा आदि उपस्थित थे।

देहरादून 08 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–04(02/23)**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार डॉ.हर्ष वर्धन ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देहरादून स्थित केन्द्रीय विद्यालय, वन अनुसंधान संस्थान का बजट पूर्व की भाँति उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आई.सी.एफ.आर.आई, देहरादून पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का स्वायत्त निकाय है, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून एवं केन्द्रीय विद्यालय, टी.एफ.आर.आई., जबलपुर आते हैं। जब तक इन दोनों विद्यालयों का विलय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नहीं हो जाता तब तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन दोनों केन्द्रीय विद्यालयों को बजट उपलब्ध कराता रहेगा।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

हरिद्वार / देहरादून 08 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(02 / 22)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरूवार को हरिद्वार के आर्यनगर में नव निर्मित राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के सह सर कार्यवाह श्री कृष्ण गोपाल तथा विश्व हिन्दू परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने संघ कार्यालय का लोकार्पण करते हुए कहा कि संघ कार्यालय के निर्माण से देशभर में हिन्दू संस्कृति के प्रसार में लगे प्रचारकों एवं स्वयं सेवकों को संघ और राष्ट्र के कार्य करने में सुगमता होगी। उन्होंने कहा कि संघ एक विचाराधारा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण, समाज का सर्वांगीण विकास तथा भारतीय संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन एवं पोषण करना है। संघ सदैव वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से कार्य करता हुआ आगे बढ़ रहा है तथा वैश्विक स्वीकार्यता प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। आज संघ सामाजिक समरसता की भावना को आगे बढाते हुए समाज को एकात्मकता प्रदान करने की दिशा में गतिशील है। संघ व्यापक रूप लेकर प्रत्येक भारतीय की जिज्ञासा व विचार में शामिल हो गया है, जो इसके पवित्र ध्येय की विजय हैं।

हरिद्वार / देहरादून 08 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(02 / 21)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरूवार को कटारपुर गौ रक्षा तीर्थ के शताब्दी वर्ष श्रद्धांजलि समारोह में प्रतिभाग किया। उन्होंने कटारपुर गांव में बने शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि यज्ञ में आहुति डाली।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, ज्वालापुर विधायक श्री सुरेश राठौर, रानीपुर विधायक श्री आदेश चौहान, रूड़की विधायक श्री प्रदीप बत्रा, हरिद्वार ग्रामीण विधायक श्री यतीश्वरानंद, मेयर श्री मनोज गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अजय भट्ट, जिलाध्यक्ष बीजेपी हरिद्वार डॉ.जयपाल चौहान सहित अनेक पदाधिकारियों ने भी यज्ञ में पूर्ण आहुति दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि कटारपुर एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां हिन्दुओं ने गौ माता को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। गाय पुरातन काल से आज तक सभी हिन्दुओं की आस्था और संस्कृति का सूत्र है। यदि धर्म और आस्था से अलग तर्क और वैज्ञानिक आधार पर बात करें, तो दिल्ली की सुप्रसिद्ध श्रीराम प्रयोगशाला में गाय सहित गौमूत्र, गोबर आदि पदार्थो पर हुए रिसर्च में यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय देसी गाय के दूध व गौमूत्र अर्क का सेवन अवसाद, माइग्रेन सहित अनके व्याधियों से निजात दिलाने में कारगर है। वहीं गाय के गौबर का प्रयोग भी त्वचा सम्बन्धी रोगों को नष्ट करने में औषधीय रूप से कार्य करता है। ब्राजील सहित दुनिया के कई देश भारतीय देसी गाय के गुणों के कारण अपने यहां पालन पोषण कर रहे हैं।

अनुपयोगी मानकर लावारिस छोड़े गये गौ वंश या बूढ़ी गायों के लिए भारत सरकार देशी गौशालाओं के संरक्षण व संवर्द्धन को प्रोत्साहन दे रही है। राज्य सरकार की ओर से नरियाल गांव चम्पावत में स्थापित गौ वंश संरक्षण केंद्र देसी नस्लों के संरक्षण में बहुत बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है। राज्य सरकार की ओर से पशुआहार के दाम 270 रूपये प्रति कुन्तल कम कर दिये गये हैं। राज्य सरकार शीघ्र ही एक सीमन केंद्र ऋषिकेश में स्थापित करने जा रही है, जहां देसी गायों के ब्रीड सुधार पर कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने 18 सितम्बर 1918 को गांव में गौवध का विरोध करने पर अंग्रेजी हुकुमत द्वारा फांसी तथा काला पानी की सजा सुनाये गये शहीदों के परिजनों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।

नोट : जिला सूचना कार्यालय, हरिद्वार से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।

देहरादून 08 फरवरी, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(02/20)

आपको कैसा बजट चाहिए, सरकार लेगी सुझाव, राज्य के 6 स्थानों पर खुद सीएम लेंगे आपकी राय

अब सरकार राज्य के बजट के लिए आपके सुझाव लेने के लिए आपके पास आ रही है। जी हां, यह पहली बार है जब उत्तराखंड में बजट से पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की पहल की है। इसके लिए राज्य के छह स्थानों पर खुद मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच जाकर उनसे बजट के लिए सुझाव लेंगे। उनके महत्वपूर्ण सुझावों और राय को सरकार बजट में शामिल करेगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए बजट सत्र भराड़ीसैंण गैरसैंण में करने का प्रस्ताव दिया है। निश्चित तौर पर राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री का यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट सत्र उत्तराखंड के इतिहास में भी दर्ज होगा। इसीलिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मन बनाया है कि क्यों न जिनके लिए बजट बनाया जा रहा है खुद उनकी आकांक्षाओं और सुझाव से ही बजट तैयार किया जाए। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र 20 मार्च से आहुत किया गया है।

मुख्यमंत्री का भी मानना है कि एक स्वस्थ और समावेशी बजट वो होता है जिसमें समाज के सभी वर्गों के सुझाव को शामिल किया जाए। इसलिए यह बेहद जरूरी है समाज के सभी वर्गों तक पहुंच कर उनके सुझाव लिए जाएं। इसके लिए लोगों को अपने सुझाव देने के लिए कहीं नहीं जाना होगा बल्कि मुख्यमंत्री जी खुद लोगों के पास जाकर उनके सुझाव और राय लेंगे।

इस कार्यक्रम को 'आपका बजट आपकी राय' नाम दिया गया है। बजट से पहले 6 चरणों में अलग–अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बीच जाकर मुख्यमंत्री जी अलग–अलग विषयों पर बजट के लिए लोगों के सुझाव मांगेंगे। उनमें से महत्वपूर्ण सुझावों को राज्य के बजट में शामिल किया जाएगा। इस कड़ी में सबसे पहले 13 फरवरी को यमुनोत्री में किसानों के बीच जाकर मुख्यमंत्री उनकी राय लेंगे।

इसके बाद पिथौरागढ़ में बजट के लिए महिलाओं के सुझाव लेंगे। अगले चरण में हरिद्वार में फिर से किसानों के बीच होंगे और उनकी बात सुनेंगे।

हल्द्वानी में पूर्व सैनिकों के बीच मुख्यमंत्री जी बजट के लिए उनके सुझाव लेंगे। अंतिम दो चरणों में देहरादून में मुख्यमंत्री जी पहले एंटरप्रेन्योर्स से और फिर युवाओं से संवाद कर बजट के लिए उनके सुझाव सुनेंगे।

इस तरह अलग–अलग भौगोलिक क्षेत्रों में समाज के अलग–अलग वर्गों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंच कर बजट पर उनकी राय सुन सकेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आम लोगों से मिले ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में शामिल किया जा सके।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।